those meant for the children, whether imported from abroad or produced in India ?

SHRIMATI NANDINI SATPATAY : Many times, films are shown for children on TV, that is, films made for children. Also films which we get from outside for the children are also shown on TV.

SHRI S. M. BANERJEE : I am talking of cartoon pictures.

SHRIMATI NANDINI SATPATHY : I do not know whether any cartoon films have been shown here, but I shall definitely look into this.

श्री आर. वी. वड़े : मंत्री महोदय ने बतलाया है कि टी वी पर दिखाई जाने वाली फिल्मों को सैंसर करने के लिए सैंसर बोर्ड में एक अफ़सर होता है जिसके कि द्वारा सैंसर होकर टी वी पर फिल्में दिखाई जाती हैं। क्या मंत्री महोदय को पता है कि अभी कल टी वी फ़ीचर फिल्म "दास्तान" के कुछ अंश दिखाये गये जोकि बहुत अश्लील थे और भद्दे थे ?

श्री एस० एम० बनर्जी : माननीय सदस्य देखने क्यों गए थे ? Unless the hon. Minister and the hon. Member have seen the picture, this question cannot be replied to. Nobody else has seen the picture.

श्री आर० वी० वड़े : अध्यक्ष महोदय, कल टी वी पर दास्तान फिल्म के जो अंश दिखाये गये थे वह निहायत ही अश्लील और भद्दे थे और वह बच्चों को तो बिलकुल ही दिखाये जाने के काबिल नहीं थे। मैं चाहता हूं कि टी वी पर दिखाई जाने वाली फिल्मों की सैंसर के लिए जो केवल एक अफ़सर नियुक्त है उसके स्थान पर पूरा सैंसर बोर्ड उनको सैंसर करे और तब ही वह टी वी पर फिल्म दिखलाई जा सकें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो वह देखी थी कोई खास बुरी नहीं थी।

एक माननीय सदस्य : बड़े साहब को बुरी लगी।

अध्यक्ष महोदय : अब उनकी उम्र नहीं है। Next question. Q. No. 577. The hon. Member is absent. Next question. Q. No. 578 Again. the hon. Member is absent. Are they really absent ?

(Interruption)

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI H. N BAHUGUNA) : They are satisfied with the answers, and, therefore, they have not come.

Setting up of Consumer Industries in Public Sector

*579. SHRI B. S. BHAURA : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) the target set for setting up consumer industries in the public during the Fourth Plan; and

(b) the names of the consumer industries set up so far during the period ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD): (a) and (b) There are already some public sector units which are manufacturing certain consumer goods (*e. g.* wrist watches, bread, common salt, newsprint, cement, drugs & pharmaceuticals, leather footwear, petroleum products, plastic cable, photo films etc.) Government have further decided that during the Fourth Five Year Plan, the role of the public sector should be expanded and extended to new fields, including consumer industries in which major production gaps are likely to develop in the coming years. With this end in view, some proposal for the manufacture of consumer goods in the public sector are under consideration and feasibility reports for some of these items have been prepared. These reports are under various stages of consideration.

श्री जान सिंह औरा : इस मंत्रालय के द्वारा जो सालाना रिपोर्ट छापी गई है उसमें बतलाया गया है कि रबड़ में हम सैल्फ सफिशिएंट नहीं हैं तो क्या मंत्री महोदय को इस बात का पता है कि रिक्शा ट्यूब टायर और दूसरे टायर ट्यूबस बाजार में ब्लैक में मिल रहे हैं तो टायर व ट्यूबों की कमी को दूर करने के लिए क्या सरकार कोई नये टायर ट्यूब्स के कारखाने लगायेगी ताकि उनकी कमी के कारण यह जो उनका ब्लैक चल रहा है वह खत्म हो सके ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : माननीय सदस्य ने जिन टायर, ट्यूब्स की बाजार में कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया है तो वह पिछले कुछ महीनों में वैगंस के आवश्यक मूवमेंट न होने के कारण वह दिक्कत हो रही थी और स्केयरसिटी कंडिशंस हो गई थी। अब एक तो वैगंस का मूवमैंट ठीक हो गया है और दूसरे स्माल स्केल के सैक्टर में टायर, ट्यूब अब काफ़ी संख्या में बनाये जा रहे हैं ; इसलिए अब उनकी कमी नहीं होगी।

श्री जान सिंह औरा : माननीय मंत्री ने बतलाया कि इधर चंद महीनों में वैगंस के न मिलने से इनकी कमी हो रही थी तो क्या उनकी जानकारी में यह बात है कि ट्यूब्स और विशेष कर रिक्शा ट्यूब्स ब्लैक में बेचे जा रहे हैं यदि हां, तो उनकी सेल पर उनका कोई कंट्रोल है या नहीं ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : अगर माननीय सदस्य इस बारे में ध्यान आकर्षित करेंगे तो उसके बारे में हम कार्यवाही करेंगे।

श्री बी. पी. मौर्य : जिस समय हम पब्लिक सैक्टर में कंज्यूमर गुड्स को लेते हैं तो क्या इस बात को ध्यान में रखा जायेगा कि जिन छोटे-छोटे धंधों में लाखों और करोड़ों गरीब इंसान लगे हुए हैं उन उद्योगों को हम पब्लिक सैक्टर में न लायें क्योंकि उन उद्योगों को पब्लिक सैक्टर में ले आने से हमें बहुत से लोगों को बेकार कर देंगे ? उदाहरण के लिए जैसे जूते बनाने का धंधा है, सूटकेस बनाने का कार्य है या जैसे चमड़े के और कार्य हैं, साबुन बनाने का कार्य या तेल बनाने का कार्य है ऐसे छोटे उद्योगों को सरकार पब्लिक सैक्टर में न लाये। पब्लिक सैक्टर में सरकार उन उद्योगों को लाये जिनमें कि बड़े-बड़े परिवार और करोड़पति और अरबपति लोग लगे हुए है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उसे ध्यान में रक्खा जायेगा।

SHRI K. GOPAL : Today many of the consumer industries are in the hands of foreign monopolists. I would cite the examples of toilets and tobacco. Will Government consider this aspect while fixing priorities for entering into these industries and see that the foreign monopoly in this sphere is broken and these units taken over ?

SHRI SIDDHESHWAR PRASAD : We are not entering this sphere, but we have licensed quite a few Indian industries which will enter in a big way into these spheres. Thus the share and dominion of the foreign companies will come down.

श्री रामावतार शास्त्री : क्या यह बात सच है कि टायर ट्यूब की कमी पटना नगर में बहुत ज्यादा है और क्या यह बात सच है कि वहां 200, 300 रुपये अधिक लेकर उसकी बिक्री हो रही है ? क्या यह बात भी सच है कि वहां के ट्रक डीलर्स असोसियेशन ने इसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और कोई मेमोरेंडम भी आप के पास भेजा है, यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : ट्रक टायरों की कठिनाई के बारे में मैंने बिहार सरकार के साथ बातचीत की थी। बिहार सरकार ने उस कठि-

नाई को हल करने के लिए कुछ आवश्यक व्यवस्था की है और उसके बाद बतलाया गया है कि स्थिति में अब काफी सुधार हुआ है।

SHRI NARSINGH NARAIN PANDEY: May I Know how the Government proposes to maintain the price line, because the consumer price index has risen from 181 to 188? I want to know whether the Government proposes to take up the production of some essential Consumer commodities in public sector ?

SHRI SIDDHESHWAR PRASAD : This is a separate question.

SHRI NARSINGH NARAIN PANDEY: This is a very important question, Sir. If the Government does not propse to maintain the price line, how can it be checked ?

(Interruption)

MR. SPEAKER : The Minister has noted this surgestion. Now, Shri Banerjee.

SHRI S.M. BANERJEE : I think the questioner has put a relevant question ; it should come under the public sector, because of the rise in the pruces of consumer goods manufactured in the private sector. So, the question put by my hon. friend Shri Pandey about the price line is important. May I know from the hon. Minister whether any decision has been taken by the Government of India to maintain the price line at a reasonable level in respect of all those commodities which are manufactured in the private sector and not taken up in the public sector ?

MR. SPEAKER : You have put the same question.

SHRI S.M. BANERJEE : Kindly ask the Minister to answer it, Sir. I want to have an idea.

Mr. SPEAKER : If the same question is put by Mr Banerjee, is there a different answer?

SHRI SIDDHESHWAR PRASAD : Whenever there is a scarcity and there is an abnormal rise in prices, under the Essential Commodities Act we issue orders and the State Goverments are supposed to take action and they are supposed to control the prices.

SHRI S.M. BANERJEE : Even in Delhi, the prices have risen; what are their doing.

श्री हुकम चन्द कछवाय : मंत्री महोदय ने मूल प्रश्न के उत्तर के अन्त में इस बात को स्वीकार किया है कि हम कुछ उद्योग खोलने पर विचार कर रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि उद्योग खोलने के सम्बन्ध में उनका विचार कब तक पूरा हो जायेगा? क्या उन क्षेत्रों का भी योजना मंत्रालय द्वारा ध्यान रक्खा जायेगा जो पिछड़े हुए माने गये हैं? विशेषकर जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के डाकू इलाकों के क्षेत्र है क्या उन में कोई उद्योग खोलने पर विचार किया जा रहा है?

अध्यक्ष महोदय : जब आप मध्य प्रदेश का नाम लिया करें तो डाकुओं का नाम मत लिया करें।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : हम लोग इस बात का ध्यान रक्खेंगे।

अध्यक्ष महोदय : जब आप मध्य प्रदेश का नाम लेते है तो डाकुओं की बात कहते हैं और जब पंजाब का नाम लेते हैं तो शराब की बात कहते हैं। यह ठीक नहीं है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मंत्री महोदय का उत्तर मेरी समझ में नहीं आया।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : माननीय सदस्य ने पिछड़े इलाकों के आर्थिक विकास की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। हम लोग उन को ध्यान में रक्खेंगे।

SHRI VASANT SATHE : In view of the large employment potential in the consumer sector, is the Government considering decentralisation of the consumer goods sector so that the small scale industries may be

able to produce more consumor goods instead of the large scale sector doing it ?

SHRI SIDDHESHWAR PRASAD : We have reserved certain items to be manufactured only in the small scale sector; there, generally new larger industrial units are not licensed, and as for as possible, we are making all efforts to see that those items are only manufactured and the demands are fulfilled by the articles manufactured in the small scale sector.

SHRI PARIPOORNANAND PAINULI: Sir the hon. Minister has made a reference to cement production. May I know from him as to what is the shortage in cement and whether he is prepared to establish a cement factory in the backward area like Dehra Dun ? A plant was under consideration in the third five year Plan.

SHRI SIDDESHWAR PRASAD . There is a marginal shortage of cement, and there is a proposal also to set up a factory at Dehra Dun.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : I want to have a specific answer to the question as to which are the sectors in the consumer industry which Government propose to take over in the fourth Plan ?

SHRI SIDDESHWAR PRASAD : We have selected certain items about which feasibility reports are being prepared. They include baby food, electric lamp and lamp-making machinery, torch cells, storage batteries, graphite and carbon products and tyres and tubes.

SHRI S. M. BANERJEE : What about Dalda and soap ?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : Government says, in principle it wants to enter the consumer sector also and a list of a few items has been given which is most unimpressive. May I know what is the total percentage of consumer goods being produced in the public sector out of the total production in the country ? Why does not Government enter into those consumer goods where the profit is the highest ?

SHRI SIDDHESHWAR PRASAD : I do not have the full figures with me at present.

Setting up of Tractor Factory in Rajasthan

*580. SHRI SHRIKISHAN MODI : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether the Central Government have taken any final decision on the letter of intent issued to set up tractor factory in Rajasthan ;

(b) whether this factory will be set up with foreign assistance ; and

(c) if so, the salient features of the scheme ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI MOINUL HAQUE CHOUDHURY) : (a) to (c). The Rajasthan State Agro-Industries Corporation, Jaipur were issued a Letter of Intent on the 9th November, 1970, for the manufacture of 'Renault' (46 HP) Agricultural tractors for a capacity of 5,000 Nos per annum in collaboration with M/s Regie Nationale Renault of France. Subsequently the Corporation informed Government that the collaboration arrangements with M/s Renault could not be finalised to mutual satisfaction and they were accordingly negotiating with other parties. A revised collaboration proposal has now been received from the Corporation and is under examination.

श्री श्रीकिशन मोदी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या कारपोरेशन ने समझौता न होने का कोई कारण बतलाया है ? कारपोरेशन ने जो प्रपोजल भेजा है वह कब तक फाइनलाइज हो जायेगा ?

SHRI MOINUL HAQUE CHOUDHURY : We have received this proposal very recently and this is under examination. It is very difficult for us to say by what time it will be finalised, because it depends on the terms on which they would like to enter into an agreement.

श्री श्रीकिशन मोदी : राजस्थान में सीकर जिला सब से बैकवर्ड एरिया है । वहां पर आज छोटे से छोटा भी कोई कारखाना नहीं है । क्या इस जिले के अन्दर यह कारखाना लगाये जाने की कोई योजना हो सकती है ?